

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-2237 / 2015

रामेश्वर प्रसाद जाट

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पंचायतीराज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, जयपुर।

—प्रत्यर्थागण

आदेश की दिनांक : 30.04.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक

प्रत्यर्था विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)

चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड—तृतीय के पद पर आदेश दिनांक 04.03.1991 के द्वारा हुई थी। अपीलार्थी ने पदभार दिनांक 07.05.1991 को ग्रहण किया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 10.05.1999 के द्वारा दिनांक 07.05.1991 से स्थायी किया गया, जिसका आदेश पंचायत समिति, प्रतापगढ, द्वारा जारी किया गया। अपीलार्थी को प्रथम एसीपी का लाभ 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम नियुक्ति की दिनांक से नहीं दिया गया बल्कि दिनांक 31.03.1999 से नियमित नियुक्ति होना मानते हुए दिया गया। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति की दिनांक 07.05.1991 मानते हुये प्रथम एवं द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है, परन्तु अपीलार्थी को दिनांक 31.03.1999 से नियमित होना मानते हुए लाभ दिया जा रहा है, जो गलत है।
2. प्रत्यर्था विभाग की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि पंचायत समितियों द्वारा शिक्षा विभाग में स्थानांतरित होकर आये कर्मचारियों की सेवाओं का नियमितीकरण स्क्रीनिंग के बाद इनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से ही कर दिये जाने के फलस्वरूप क्या इन कर्मचारियों की सेवायें भूतलक्षी प्रभाव से नियमित मानी जा सकती है। इस संबंध में विशिष्ट शासन सचिव, शिक्षा (गुप-5) विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक :-प.18(4)

- शिक्षा-5/98 दिनांक 06.02.1999 से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन संबंधी अधिसूचना क्रमांक:- 4(11)पी.एण्ड जे/आरडी./पी/87 192 दिनांक 17.03.1989 के अनुसार ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति स्क्रीनिंग के बाद आदेश जारी किये जाने की तिथि से ही नियमित मानी जावेगी। इस प्रकार अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति स्क्रीनिंग आदेश जारी होने की तिथि दिनांक 31.03.1999 से ही नियमित मानी गयी है।
3. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।
 4. अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति जो दिनांक 07.05.1991 को हुई थी, वह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी थी, जिस आदेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित था कि अपीलार्थी की नियुक्ति अस्थायी तौर पर है तथा उक्त अवधि के बीच प्रशिक्षित चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। अपीलार्थी को बाद में आदेश दिनांक 31.03.1999 के द्वारा स्थायी किया गया एवं स्थायीकरण की दिनांक से अपीलार्थी को नियमित माना गया।
 5. माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 589/2015 राजस्थान राज्य बनाम चन्द्रा राम में पारित तीन न्यायाधिपति की पीठ के निर्णय दिनांक 03.07.2017 का अवलोकन करें तो उक्त निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्न बिन्दुओं पर अपना निर्णय दिया है :-

- (a) Whether the respondents stand regularized from the date of appointment after scrutiny by the District Establishment Committee?
- (b) Whether their order of regularization is still valid or has been annulled?
- (c) Whether the appellants can assail the order of regularization without having actually annulled it till today?
- (d) Whether there can be two dates for regularization of an employee, retrospective for some purposes and prospective for others?
- (e) Does Goparam (supra) lay down the correct law in distinguishing Jagdish Narain Chaturvedi (supra) and Surendra Mohnot (supra)?"

उपरोक्त बिंदुओं पर माननीय उच्च न्यायालय से निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :-

37. QUESTION A For the reasons and discussions aforesaid and in view of the law declared by the Supreme Court in the case of Jagdish Narain Chaturvedi and Surendra Mahnot & Ors. (supra); we are of the opinion that the respondent - employee would stand regularized from the date of regularization in service and not prior to that.

38. QUESTION B Taking into consideration the recent decision, prior to two decades the regularization period was not questioned by anybody, therefore, in a writ petition filed by the petitioner it will not be appropriate for us to allow the

Government to end the regularization. However, regularization will be from the date of regularization done by the department and not prior thereto.

39. QUESTION C The contention of the counsel for the employees is required to be accepted and it cannot be annulled unless it has been annulled by appropriate authority. However, the benefits shall not be withdrawn but in future when the benefits are to be accorded for further promotion, the same will be considered on the basis of new law declared by the Supreme Court i.e. period will be considered from the date of regularization. When the future benefit of 9, 18 and/or 27 will be considered their ad-hoc service will not be considered for the purpose of benefit of 9, 18 and/or 27 years. But if benefit has already been granted for all the three scales; the same shall not be withdrawn and no recovery will be made from the employees.

40. QUESTION D In view of our answer in above matters, it is very clear that for the purpose of regularisation the date of regularisation will be from the date of regular appointment. In that view of the matter, there cannot be two dates for the purpose of seniority and the other benefits. However, earlier services will be considered for the purpose of the same if there is a shortage in pensionary benefits.

41. QUESTION E In view of the observations made by the Supreme Court, as referred to above, the ad-hocism will not be considered for seniority. In that view of the matter, there will be only one date for regularization, date of regularizing ad-hoc period will not have any effect on seniority. In our considered opinion, the Division Bench of this Court in the case of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram in DB Civil Special Appeal No.44/2016, decided on 18.04.2016 had no right to distinguish the judgment of the Supreme Court in the case of Jagdish Narayan Chaturvedi (Supra) and State of Rajasthan vs. Surendra Mohnot & Ors. (supra). Thus, the decision of State of Rajasthan & Ors. vs. Gopa Ram (supra) did not lay down correct law. The correct law would be the law declared by the Supreme Court in the two judgments referred hereinabove.

6. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना है कि नियमितकरण की दिनांक से ही कार्मिक की सेवाएं मानी जानी चाहिए। हम पाते हैं कि अपीलार्थी को स्क्रीनिंग के पश्चात नियमित किये जाने के पश्चात ही सेवाएं चयनित वेतनमान के लिए गिनी जा सकती है। अतः अपीलार्थी की जो सेवाएं दिनांक 31.03.1999 से नियमित मानी गयी है, उसी दिनांक से अपीलार्थी चयनित वेतनमान एवं अन्य लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। उससे पूर्व की सेवाएं अपीलार्थी चयनित वेतनमान के लिये नहीं जुड़वा सकता है।
7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)